गरवी गुजरात

RNI No.: UPHIN/25/A1697

GARVI GUJARAT

गरवी गुजरात

लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 208
दि. 29.11.2025,
शनिवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.

Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

योगी सरकार का फैसला, कुशीनगर का ऐतिहासिक फाजिलनगर अब होगा पावा नगरी !

(जीएनएस)।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से पहले एक बार फिर नाम बदलने की सियासत तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार कुशीनगर जिले के ऐतिहासिक फाजिलनगर गांव का नाम बदलकर 'पावा नगरी' करने का ऐलान किया है. योगी सरकार के इस फैसले ने एक बार फिर 'नाम बदलो सियासत' को हवा दे दी है. हिंदूवादी संगठन और बीजेपी नेताओं का दावा है कि नाम बदलने से इस इलाके का तेजी से विकास होगा.

उत्तर प्रदेश की दक्षिणपंथी सरकार का आए दिन पूर्व नामों से नफरत सामने आ ही जाता है. हालिया कुछ सालों में योगी सरकार ने मुस्लिम समुदाय से जुड़े हुए ऐतिहासिक और उर्दू नामों को बदल दिया है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यानाथ ने कुशीनगर जिले के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलने का ऐलान किया है. सीएम योगी के इस ऐलान ने एक बार फिर 'नाम बदलने की परंपरा' को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

दरअसल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलकर 'पावा नगरी' करने का ऐलान किया है. इसे यूपी कैबिनेट की अगली बैठक में अब अमलीजामा पहनाया जाएगा. शहरों और कस्बों के नाम बदलने के क्रम में फाजिलनगर, कुशीनगर में ऐसी पहली जगह होगी, जिसका नाम बदलकर 'पावा नगरी' किया गया है.

दावा किया जा रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण इसी पावा नगरी में हुआ था. आज भी यहां उनके नाम पर

मंदिर और अंतिम संस्कार स्थल मौजूद है, इसलिए हिंदूवादी संगठन इस कस्बे का नाम दोबारा पावा नगरी करने की मांग कर रहे थे. इसके बाद दक्षिणपंथियों की मांगों को मानते हुए योगी आदित्यनाथ ने नाम बदलने का ऐलान किया है.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में आयोजित पार्श्वनाथ जी के मंदिर और मूर्ति के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे. इस कार्यक्रम के दौरान अपने संबोधन में कुशीनगर के फाजिलनगर नगर पंचायत का नाम बदलकर पावा नगरी करने का ऐलान किया. बीजेपी समर्थक और हिंदूवादी संगठन इस फैसले को ऐताहिकासिक करार दे रहे हैं.

इस पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मिल रही है. बीजेपी और हिंदूवादी संगठन के लोगों का मानना है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के नाम पर इस नगर का नाम होने से नगर का जोरशोर से विकास होगा. हैराने करने वाली बात यह है कि उन्होंने दावा किया कि इतिहास में इस कस्बे के साथ छेड़छाड़ हुई थी. उन्होंने दावा किया कि मुगल आक्रांताओं के नाम पर इस ऐतिहासिक नगर का नाम बदलकर फाजिलनगर किया गया था वो भी दुरुस्त होगा.

'दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो तबाह कर देगा हमारा सुदर्शन चक्र', पीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उडुपी दौरे के दौरान श्री कृष्ण मठ में लक्ष कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में शामिल हुए. सुवर्ण तीर्थ मंडप और कनक कवच का उद्घाटन करने के बाद पीएम ने बताया कि गीता श्लोक से मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है.

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कर्नाटक दौरे में भारतीय संस्कृति में उडुपी के योगदान की जमकर सराहना की. श्री कृष्ण मठ और लक्ष कंठ गीता पारायण प्रोग्राम में प्रधानमंत्री मोदी ने भगवदगीता के महत्व को लेकर चर्चा की. इस दौरान पीएम ने पहलगाम हमले और सुदर्शन चक्र (राष्ट्रीय सुरक्षा कवच) का जिक्र किया. उन्होंने कहा कि दुश्मन दुस्साहस दिखाएगा तो हमारा सुदर्शन चक्र तबाह कर देगा.

पीएम ने कहा, 'उडुपी की धरती पर आना हमेशा अलग से अनुभूति देता है. यहां आना मेरे लिए एक और वजह से विशेष है. उडुपी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की कर्मभूमि रही है. इसने नए गवर्नेंस मॉडल की नींव रखी थी. जल आपूर्ति और ड्रेनेज सिस्टम की शुरूआत सत्तर के दशक में ही कर दी थी. आज यह अभियान देश के विकास की प्राथमिकता का मार्गदर्शन कर रहा है.'

'गीता के श्लोक से मन को आध्यात्मिक शक्ति'

उन्होंने बताया, 'जब एक लाख कंठ गीता के श्लोकों का उच्चारण करते हैं, गीता जैसे पुण्य ग्रंथ का पाठ करते हैं. इतने दैवीय शब्द एक साथ गूंजती है तो ऐसी ऊर्जा निकलती है तो हमारे मन और मस्तिष्क को संबल देती है. यही ऊर्जा मन को आध्यात्मिक शक्ति देती है.'

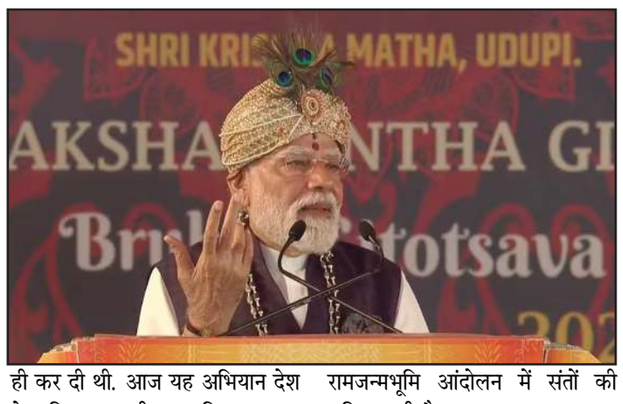

अयोध्या से उडुपी तक रामजन्मभूमि आंदोलन में संतों की भूमिका रही है.

उडुपी के लिए राम मंदिर का निर्माण एक और कारण से विशेष है. नए मंदिर में वेदांत के प्रकाश स्तंभ जगदुरु माधवाचार्य को भी जगह दी गई है.

इस दौरान पीएम ने कृष्ण मंदिर के सामने बने सुवर्ण तीर्थ मंडप का भी उद्घाटन किया और पवित्र कनकना किंदी के लिए कनक कवच समर्पित किया. यह 100,000 लोगों का एक भक्ति कार्यक्रम था, जिसमें स्टूडेंट्स, साधु, विद्वान और अलग-अलग तरह के लोग शामिल हुए.

यह है महत्व

माना जाता है कि इसी पवित्र खिड़की से संत कनकदास को भगवान कृष्ण के दिव्य दर्शन हुए थे. उडुपी में श्री कृष्ण मठ की स्थापना 800 साल पहले वेदांत के द्वैत दर्शन के संस्थापक श्री माधवाचार्य ने की थी.

गोवा का कार्यक्रम...

इसके बाद, पीएम मोदी सारधा पंचाष्टमोत्सव के मौके पर गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण परतगली जीवोत्तम मठ के 550वें साल के जश्न में हिस्सा लेंगे. मठ में कांसे से बनी श्री राम की 77 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण करेंगे और रामायण थीम पार्क गार्डन का उद्घाटन करेंगे. इस मौके पर, प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित भी करेंगे और खास पोस्टल स्टैम्प और एक यादगार सिक्का जारी करेंगे.राष्ट्रपति ने 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह में भाग लिया

राष्ट्रपति ने भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती के समापन समारोह में भाग लिया

(जीएनएस)।

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारत स्काउट्स और गाइड्स के हीरक जयंती के समापन समारोह में भाग लिया और इसकी 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी को संबोधित किया।

इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि यह गर्व का विषय है कि पिछले 75 वर्षों से भारत स्काउट्स और गाइड्स युवाओं का मार्गदर्शन कर रहा है और उन्हें राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्होंने रेखांकित किया कि सेवा की भावना स्काउट्स और गाइड्स की सबसे बड़ी ताकत है। चाहे बाढ़ हो, भूकंप हो या कोई महामारी, स्काउट्स और गाइड्स हमेशा सहायता के लिए सबसे आगे रहते हैं। इस संगठन की एक और विशेषता राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। उन्होंने युवाओं को सशक्त, संवेदनशील और देश के भविष्य के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध बनाने हेतु भारत स्काउट्स और गाइड्स की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट्स और गाइड्स हैं, जो भारत स्काउट्स और गाइड्स को दुनिया के सबसे बड़े स्काउट्स और गाइड्स संगठनों में से एक बनाता है। उन्हें यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इस संगठन से 24 लाख से अधिक लड़कियां जुड़ी हैं। उन्होंने अनुशासन, समर्पण और समाज व मानवता के कल्याण का मार्ग चुनने के लिए उन सभी लड़कियों की सराहना की।

राष्ट्रपति ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स का आदर्श वाक्य "तैयार रहो" है। इसका मतलब है कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने टी-20 क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय महिला दृष्टिबाधित खिलाड़ियों से बातचीत की

प्रधानमंत्री ने चुनौतियों पर विजय पाते हुए आत्मविश्वास के साथ प्रतिभा और राष्ट्रीय गौरव का प्रदर्शन करने के लिए खिलाड़ियों की सराहना की

कड़ी मेहनत खेल के मैदान से परे जीवन में भी सफलता सुनिश्चित करती है: प्रधानमंत्री

टीम की उपलब्धियां सभी को प्रेरित करती हैं और देश के युवाओं की शक्ति व दृढ़ता को उजागर करती हैं: प्रधानमंत्री

प्रविष्टि तिथि: 28 ठडश 2025

रायपुर पहुंचे पीएम मोदी, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी सिक्योरिटी मीटिंग में होंगे शामिल

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार शाम तीन दिनों के दौरे पर रायपुर पहुंचे. पीएम मोदी यहां पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रही देश की सबसे अहम DGP-IGP कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे. प्रधानमंत्री अपने प्रवास के दौरान विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक प्रदान करेंगे. साथ ही वे कक्षा 9वीं और 12वीं के 25 से 30 विद्यार्थियों से भी मुलाकात कर सकते हैं. इस हाई-प्रोफाइल कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ठरअ अजीत डोभाल और देशभर के टॉप पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे.

पीएम मोदी शुक्रवार शाम रायपुर पहुंचे.

रायपुर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को तीन दिवसीय प्रवास पर रायपुर पहुंचे है. वे 29-30 नवंबर को रायपुर स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM), रायपुर में होने वाले 60वें अखिल भारतीय डीजीपी/आईजीपी सम्मेलन में भाग लेंगे. इस बार देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है. माना एयरपोर्ट से पीएम मोदी सीधे नवा रायपुर स्थित स्पीकर हाउस पहुंचे. इस वर्ष सम्मेलन का विषय है विकसित भारत- सुरक्षा आयाम. इसका उद्देश्य पुलिसिंग से जुड़े बड़ी चुनौतियों की समीक्षा करना है. साथ ही सुरक्षित भारत का

नया रोडमैप तय करना है.

पीएम मोदी शनिवार और रविवार को होने वाले मुख्य सत्रों में शामिल होंगे. वे समापन समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक भी प्रदान करेंगे. कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे. राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मुख्य सत्रों में हिस्सा लेंगे. देशभर के DGP और IGP इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ रहे हैं. छत्तीसगढ़ के लिए यह सम्मेलन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राज्य कई वर्षों से नक्सल चुनौतियों का सामना करता रहा है. इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा पर यह गंभीर चर्चा अहम मानी जा रही है.

पीएम मोदी इस कॉन्फ्रेंस में हमेशा गहरी रुचि दिखाते हैं. वे अधिकारियों से सीधे संवाद करते हैं. प्रतिभागियों को नीति प्रस्ताव रखने का अवसर मिलता है. चर्चा के बड़े मुद्दों में नक्सलवाद शामिल है.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्षगांठ समारोह को संबोधित किया

■ श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ अपनी स्थापना की 550वीं वर्षगांठ मना रहा है, यह वास्तव में एक ऐतिहासिक अवसर है। पिछले 550 वर्षों में, इस संस्था ने समय के कितने चक्रवात झेले हैं; युग बदला, दौर बदला, देश और समाज में कई परिवर्तन हुए, फिर भी, बदलते समय और चुनौतियों के बीच, मठ ने कभी अपनी दिशा नहीं खोई, इसके विपरीत, यह मठ लोगों को रास्ता दिखाने वाले एक मार्गदर्शक केंद्र के रूप में उभराः प्रधानमंत्री

■ ऐसे समय भी आए जब गोवा के मंदिरों और स्थानीय परंपराओं को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जब भाषा और सांस्कृतिक पहचान पर दबाव बना, फिर भी, ये परिस्थितियाँ समाज की आत्मा को कमजोर नहीं कर सकीं; बल्कि उसे और भी मजबूत बनायाः प्रधानमंत्री मोदी

■ यह गोवा की अनूठी विशेषता है

– कि इसकी संस्कृति ने हर बदलाव के बावजूद अपने सार को बचाए रखा है और समय के साथ खुद को फिर से जीवंत भी किया है; इस यात्रा में परतगली मठ जैसी संस्थाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई हैः प्रधानमंत्री

■ आज, भारत एक अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है, अयोध्या में राम मंदिर का जीर्णोद्धार, काशी विश्वनाथ धाम का भव्य कायाकल्प और उज्जैन में महाकाल महालोक का विस्तार – ये सभी हमारे राष्ट्र के जागरण को दर्शाते हैं, जो अपनी आध्यात्मिक विरासत को नई शक्ति के साथ उभार रही हैः प्रधानमंत्री मोदी

■ आज का भारत अपनी सांस्कृतिक पहचान को नए संकल्प और नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ा रहा हैः प्रधानमंत्री

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज गोवा में श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगली जीवोत्तम मठ के 550वें वर्ष समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पावन अवसर पर उनका मन गहन शांति से भर गया है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि संतों के सान्निध्य में बैठना अपने आप में एक आध्यात्मिक अनुभव है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने धरमपुर में 'वोकेलशनल ट्रेनिंग सेंटर' का दौरा किया : वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मुख्यमंत्री का अभिवादन समारोह आयोजित

■ मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए

■ कौशल, नवाचार और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, भारत के युवाओं में ये तीनों गुण और क्षमताएं मौजूद हैं : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल :-

■ राज्य के आदिवासी क्षेत्रों में पीपीपी मोड पर 8 अत्याधुनिक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए

■ दो दशक पहले अंबाजी से उमरगाम तक के आदिवासी बेल्ट में एक भी साइंस कॉलेज नहीं था, जबकि आज दो दर्जन साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स कॉलेज संचालित हैं

■

आदिजाति विभाग के साथ पीपीपी मोड से जुड़ा प्रमुख स्वामी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, मुख्यमंत्री ने जनभागीदारी के क्षेत्र में जुड़ाव का प्रमाण पत्र प्रदान किया

गांधीनगर, 28 नवंबर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को धरमपुर में ह्यप्रमुख स्वामी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर-पीएसवीटीसीह्न का दौरा कर प्रशिक्षु विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रमुख स्वामी महाराज की जयंती के अवसर पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ओर से मुख्यमंत्री का अभिवादन समारोह आयोजित किया गया।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज ने पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा के सद्गुणों का संदेश फैलाया है। इतना ही नहीं, स्वामीनारायण संप्रदाय ने भारतीय ऋषि संस्कृति को बचाने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने युवाओं को व्यसन मुक्त और सुसंस्कारी के साथ-साथ आत्मनिर्भर बनाने के लिए वर्षों से महाअभियान चला रहे स्वामीनारायण संप्रदाय की सराहना की।

उन्होंने कहा कि कौशल, नवाचार और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। भारत के युवाओं में मौजूद इन तीनों गुणों और क्षमता का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने गर्व से कहा कि हमारा युवा ह्यस्किल, विल और जीलह्न यानी कौशल, इच्छाशक्ति और जोश के बल पर पत्थर से भी पानी निकालने में समर्थ है।

सम्पादकीय

पुतिन की भारत यात्रा

रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन की 5 दिसम्बर को होने वाली नई दिल्ली यात्रा पर कई देशों की नजरें टिकी हैं। अमेरिका, यूरोपीय देश और चीन के लिए यह पुतिन प्रवास अत्यन्त महत्वपूर्ण है। दरअसल पुतिन की यात्रा का मुख्य मुद्दा तो उसका तेल व्यापार है, जबकि दूसरा मुद्दा भारत को रूसी तेल पर छूट जारी रखने का प्रस्ताव और तीसरा मुद्दा रक्षा और ऊर्जा सहयोग पर विचार है। असल में रूस के व्रूड आयल पर लगे प्रतिबंधों के बाद भी रूसी तेल आयात करना भारत के लिए मुश्किल होगा किन्तु रूस चाहता है कि भारतीय वंपनियों को इस बात से आश्वस्त कराया जाए कि उसे पहले जो छूट मिलती थी वह जारी रहेगी। भारत ने रूस से मिलने वाली छूट के कारण ही व्रूड आयल के आयात में वृद्धि की है। 2021 में भारत का रूस से अपने वुल व्रूड आयल आयात का मात्र 3 प्रतिशत था जबकि यह आयात 2024 में 37 प्रतिशत तक पहुंच गया जबकि अक्टूबर 2025 में यह आयात 38 प्रतिशत पहुंच गया जो चीन 47 प्रतिशत के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है। 2025 में रूस का सकल घरेलू उत्पाद यानि जीडीपी एक प्रतिशत से भी नीचे रहने का अनुमान है और अनुमान यह भी है कि महंगाई की दर आठ प्रतिशत से भी ज्यादा है। रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध के कारण लगे प्रतिबंध की वजह से चौपट हुई पड़ी है। रूस की तेल उद्योग की तरफ से दिया जाने वाला टैक्स वहां के वुल राजस्व का 40 प्रतिशत होता है। मास्को इस बात को अच्छी तरह जानता भी है कि भारत जैसे खरीददार का विकल्प अभी रूस को मिलना मुश्किल है। भारतीय तेल वंपनियां रूस से तेल इसलिए ज्यादा खरीदती हैं, क्योंकि रूस भारत को विशाल बाजार मानकर भारतीय वंपनियों को भारी छूट देता है। भारत इस बात को अच्छी तरह जानता है कि वह अमेरिकी दबाव को ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से जब रूसी तेल आयात करने पर 25 प्रतिशत का टैरिफ लगाया था तब भी नई दिल्ली ने परवाह नहीं की थी। किन्तु मौजूदा विश्व राजनीति में अमेरिका की भूमिका को देखते हुए भारत उसकी उपेक्षा नहीं कर पाएगा। भारत ने उस समय अमेरिकी अधिकारियों को टका सा जवाब देते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने अमेरिका को सलाह दी कि रूस के तेल आयात पर प्रतिबंध तो लगा नहीं है आखिर भारत को ही रूसी तेल आयात पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अमेरिका को भारत की बात बुरी लगी इसलिए उसने रूसी तेलों पर जब प्रतिबंध लगाया तो भारत के लिए जरूरी है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पूंक कर कदम रखे। यही कारण है कि भारत को अपना रूसी तेल आयात की मात्रा कम करनी ही पड़ेगी। यही कारण है कि रूसी नेता पुतिन भारत को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास करेंगे कि भारत जैसे देश को अमेरिका से डरने की जरूरत नहीं है। तेल आयात करने के मुद्दे के साथ-साथ भारत रूस से यह गारंटी भी चाहता है कि रक्षा उपकरण भारत और रूस तैयार करते हैं, उन्हें किसी ऐसे देश को न बेचा जाए जो किसी भी तरह पाकिस्तान के साथ संपर्व में हों। उदाहरण के लिए ब्र१ोस को दोनों देशों ने विकसित किया है। कई ऐसे देश ब्र१ोस को चाहते हैं जो किसी न किसी रूप में पाकिस्तान और चीन के प्रभाव में हैं। इसलिए जरूरी है कि ब्र१ोस की ब्रिवे पर दोनों देशों की सहमति बने। लब्बोलुआब यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण हो चुकी है।

भारत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी चाय की नयी किस्में विकसित करनी चाहिएः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल

श्री गोयल ने चाय उद्योग में गुणवत्ता, पता लगाने की क्षमता और किसान कल्याण को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी अपनाने का आग्रह किया

श्री गोयल ने भारत के चाय क्षेत्र में टिकाऊ खेती, पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग और अधिक मूल्यवर्धन का आह्वान किया

(जीएनएस)।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में संकल्प फाउंडेशन के सुरक्षित चाय उत्पादन पर राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को दार्जिलिंग, असम और नीलगिरि जैसी प्रतिष्ठित चायों के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, लेकिन देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन योग्य उत्पादों की एक व्यापक सूची विकसित करना महत्वपूर्ण है।

श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी पारंपरिक क्षमताओं से आगे बढ़कर नए विशिष्ट मिश्रणों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो बदलते उपभोक्ता स्वाद, उभरते स्वास्थ्य रुझानों और दुनिया भर के उत्कृष्ट जीवनशैली बाजारों के अनुरूप हों। उन्होंने जोर देकर कहा कि उच्च गुणवत्ता वाली चाय और निम्न एमआरएल स्तर बनाए रखने के लिए स्थायी विधियों, ज़िम्मेदार श्रम मानक और निरंतर नवाचार आवश्यक हैं।

उन्होंने शोधकताओं और वैज्ञानिकों से भारत की विविध कृषि-जलवायु क्षमताओं का लाभ उठाकर नवीन किस्में और उच्च-मूल्य वाले उत्पाद विकसित करने का आग्रह किया, जिससे निर्यात के नए अवसर खुल सकें। उन्होंने कहा कि इस तरह के नवाचार-संचालित मूल्य संवर्धन से न केवल भारत की वैश्विक उपस्थिति बढ़ेगी, बल्कि किसानों—विशेषकर छोटे उत्पादकों—को बेहतर लाभ प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि निरंतर शोध, प्रयोग और उत्पाद विकास यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे कि भारतीय चाय तेजी से गतिशील होते वैश्विक चाय उद्योग में प्रतिस्पर्धी, विशिष्ट और भविष्य के लिए तैयार रहे।

श्री गोयल ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे बड़े चाय उत्पादकों और निर्यातकों में से एक है, जहाँ सालाना लगभग 255 मिलियन टन चाय का निर्यात होता है। उन्होंने जो भारत की आतिथ्य और व्यापार संस्कृति में एक अभिन्न भूमिका निभाने वाले इस प्रमुख उद्योग की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया और कहा कि सम्मेलन के दौरान हुए विचार-विमर्श से मंत्रालय और चाय बोर्ड को इस क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए बहुमूल्य जानकारी मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में की जा रही पहल छोटे चाय उत्पादकों, श्रमिकों और संबद्ध हितधारकों को सहयोग देने पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि चाय भारत के सामाजिक ताने-बाने में गहराई से समाई हुई है और परिवारों एवं समुदायों को एक साथ लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार चाय उत्पादकों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रभावी नीतियों को आकार देने में हितधारकों, शोधकताओं और उद्योग जगत के दिग्गजों से प्राप्त

जानकारी, सुझाव और मार्गदर्शन अमूल्य हैं। उन्होंने चाय उत्पादकों और श्रमिकों को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सरकार के 1,000 करोड़ रुपए के पैकेज और चाय सहयोग ऐप जैसी का उल्लेख किया, जो छोटे उत्पादकों को उनकी उपज के बेहतर मूल्य प्राप्त करने में सक्षम बनाती हैं।

उन्होंने चाय आपूर्ति श्रृंखला में पूर्ण ट्रेसेबिलिटी की आवश्यकता पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि भारतीय चाय की गुणवत्ता को तोड़ने और प्रसंस्करण से लेकर पैकेजिंग और निर्यात तक के प्रत्येक चरण में सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने शोधकताओं, उद्योग के हितधारकों और युवा उद्यमियों से ब्लॉकचेन जैसी उभरती तकनीकों का पता लगाने का आग्रह किया ताकि संपूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रणालियाँ उत्पादन चक्र के प्रत्येक चरण को रिकॉर्ड कर सकती हैं, जिससे चाय के प्रत्येक बैच के सटीक स्रोत, ग्रेड और गुणवत्ता की पहचान करने, निम्न-गुणवत्ता वाली या आयातित किस्मों के साथ मिश्रण को रोकने और यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि केवल प्रामाणिक भारतीय मिश्रण ही उपभोक्ताओं तक पहुंचें। उन्होंने आगे कहा कि मजबूत ट्रेसेबिलिटी वैश्विक स्तर पर शीर्ष चाय उत्पादक देश के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखेगी। अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के बीच अधिक विश्वास पैदा करेगी और किसानों तथा छोटे उत्पादकों के लिए बेहतर मूल्य सुनिश्चित करेगी।

श्री गोयल ने नवीन और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि ड्रिप सिंचाई जैसी विधियाँ उत्पादकों के लिए जल दक्षता और समग्र उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चाय क्षेत्र का भविष्य खेती और प्रसंस्करण के हर चरण में पर्यावरण के प्रति ज़िम्मेदार दृष्टिकोण अपनाने पर निर्भर करता है। उन्होंने हितधारकों से जैव-निम्नीकरणीय और पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग विकल्पों का पता लगाने का भी आग्रह किया और कहा कि ऐसे उपायों से उद्योग को वैश्विक स्थिरता की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों में मूल्यवर्धित, ब्रांडेड और पैकेज्ड चाय की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता दोहराई और इस बात पर जोर दिया कि भारत को अपनी वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए कमोडिटी निर्यात से आगे बढ़ना होगा। उन्होंने आश्वासन दिया कि मंत्रालय और चाय बोर्ड व्यापार मेलों, अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी सहित वैश्विक आउटरीच पहलों को पूरा समर्थन देंगे।

उन्होंने हितधारकों से चाय उत्पादक क्षेत्रों में बच्चों के लिए अवसरों को बेहतर बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया कि दीर्घकालिक क्षेत्रीय प्रगति में सामाजिक विकास भी शामिल होना चाहिए। श्री गोयल ने किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और बेहतर आय सुनिश्चित करने में कौशल विकास पहलों, मशीनीकरण और आधुनिक उपकरणों के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मौसम संबंधी बदलावों और कीट-संबंधी जोखिमों का पूर्वानुमान लगाने के लिए प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणालियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के बुद्धिमत्ता-आधारित दृष्टिकोण समय पर कृषि संबंधी निर्णय लेने और उत्पादकों को चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से प्रबंधन करने में मदद करने के लिए आवश्यक हैं।

केंद्रीय मंत्री ने चाय के प्रत्येक प्याले की उत्पत्ति, प्रक्रिया और विशिष्टता को उजागर करके चाय विपणन में नवीन वर्णनात्मक शैली को शामिल करने का सुझाव दिया। उन्होंने उद्योग से उच्चतम गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों की पहचान करने का भी आग्रह किया और आश्वासन दिया कि एफएसएसएआई, बीआईएस और ईआईसी देश भर में विश्व स्तरीय परीक्षण सुविधाओं की स्थापना में सहयोग के लिए तैयार हैं।

श्री गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार और उद्योग जगत को एक टीम के रूप में काम करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भारतीय चाय का हर कप गुणवत्ता, विरासत और विश्वास का प्रतीक हो। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि अमृत काल के दौरान विकसित भारत 2047 की भारत की यात्रा में चाय क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ।

श्री पीयूष गोयल ने फिक्की की 98वीं वार्षिक आम बैठक में दुनिया के सभी प्रमुख व्यापारिक देशों के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं पर प्रकाश डाला, कहा- व्यापार संबंध मजबूत हो रहे हैं

आत्मनिर्भरता देश की आर्थिक रणनीति के केंद्र में है: श्री पीयूष गोयल

100 अरब अमेरिकी डॉलर के ईएफटीए निवेश से राष्ट्र के नवाचार और सटीक विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा: श्री गोयल

12 अरब डॉलर के अनुसंधान कोष के साथ भारत उभरती प्रौद्योगिकियों में नेतृत्व की स्थिति में: श्री गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरीशस, यूनाइटेड किंगडम और चार देशों के ईएफटीए समूह के साथ संतुलित और न्यायसंगत व्यापार समझौते किए हैं। उन्होंने बताया कि अभी अमेरिका, यूरोपीय संघ, खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) में शामिल देशों और न्यूजीलैंड, इस्राइल, यूरेशिया, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका तथा मकोर्सुर समूह सहित लगभग 50 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 14 देशों के साथ बातचीत कर रहा है। श्री गोयल ने आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ (फिक्की) की 98वीं वार्षिक आम बैठक को संबोधित करते हुए ये बातें कही।

श्री गोयल ने भगवद् गीता और महात्मा गांधी के स्वदेशी पर जोर का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता का विचार भारत के सभ्यतागत लोकाचार का केंद्रबिंदु है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता ने ऐतिहासिक रूप से भारत की प्रगति का मार्गदर्शन किया है और यह देश की आर्थिक रणनीति का भी केंद्रबिंदु बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत पर ध्यान केंद्रित करने से यह दृष्टिकोण और भी मजबूत हुआ है।

हाल ही में हुए ईएफटीए समझौते का उल्लेख करते हुए, केंद्रीय मंत्री श्री गोयल ने कहा कि इस समूह ने नवाचार और सटीक विनिर्माण के क्षेत्र में भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार में भारत की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत में किए जाने वाले उच्च-गुणवत्ता वाले नवाचार यूरोप या अमेरिका की तुलना में बहुत कम लागत पर हासिल किए जा सकते हैं।

कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों के शीघ्र संचालन के लिए त्वरित अन्वेषण की दिशा में एक और कदम उठाया

सरकार ने कोयला क्षेत्र को मजबूत करने और भारत को आत्मनिर्भर भारत के विजन के करीब लाने के अपने निरंतर प्रयास के अंतर्गत कोयला खदानों की खोज और संचालन में तेजी लाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे प्रावधान के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय गुणवत्ता परिषद-राष्ट्रीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त निजी संस्थाओं को 26 नवंबर 2025 को मान्यता प्राप्त पूर्वेक्षण एजेंसियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस संबंध में कोयला मंत्रालय द्वारा प्रकाशित अधिसूचना मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

इससे कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए 18 और एजेंसियां जुड़ जाएंगी, जिससे कोयला ब्लॉक आवंटियों को कोयला और लिग्नाइट की खोज के लिए इन एजेंसियों को नियुक्त करने में अधिक विकल्प मिलेगा। कोयला खदान के संचालन के लिए भूगर्भीय रिपोर्ट का अन्वेषण और तैयारी एक पूर्व शर्त है। इन अन्वेषण एजेंसियों के जुड़ने से लगभग 6 महीने का समय बचेगा, जो पहले एजेंसी द्वारा लाइसेंस प्राप्त करने में लगता था।

अधिकृत संभावित एजेंसियों के समूह का विस्तार करके, सरकार निजी क्षेत्र के संसाधनों का उपयोग करना और अन्वेषण में दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देना चाहती है।

उम्मीद है कि इस कदम से अन्वेषण की गति में काफी तेजी आएगी और खनन को जल्दी बढ़ाने में मदद मिलेगी जिससे संसाधन विकास में तेजी आएगी और देश के लिए कोयला और लिग्नाइट की उपलब्धता बढ़ेगी। इससे देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए कोयला और लिग्नाइट की बढ़ती उपलब्धता में योगदान मिलेगा।

भारत सरकार एक पारदर्शी, कुशल और भविष्य के लिए तैयार खनिज अन्वेषण ढांचे को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है जो राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा और आर्थिक विकास को गति देगा।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ) 2025 समावेशन, सुदृढ़ डिजिटल ढांचे और जिम्मेदार एआई के लिए स्पष्ट विजन के साथ संपन्न

(जीएनएस)।

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम (आईआईजीएफ-2025) का पाँचवाँ संस्करण आज इंडिया हैबिटैट सेंटर और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में दो-दिन की चचाओं के साथ संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में केंद्रीय मंत्रालयों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, नागरिक समाज संगठनों, विश्वविद्यालयों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और भारत में एक खुले, विश्वसनीय और समावेशी इंटरनेट इकोसिस्टम कैसे विकसित किया जाए, इस पर विचार-विमर्श किया।

'विकसित भारत के लिए समावेशी और सतत इंटरनेट गवर्नेंस को आगे बढ़ानाह्व विषय-वस्तु के अनुरूप फोरम ने तीन उप-विषयों—समावेशी डिजिटल भविष्य, लचीले और सतत विकास के लिए डिजिटल अवसंरचना और लोगों, दुनिया और विकाश के लिए एआई—की समीक्षा की। पैनल और कार्यशालाओं में ग्रामीण कनेक्टिविटी, ओपन डिजिटल सिस्टम, डोमेन नेम और डीएनएस सुरक्षा, साइबर सुरक्षा तैयारी, भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का विकास, डेटा संरक्षण, सामग्री विनियमन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नैतिक उपयोग तथा युवा इन्नोवेटर के लिए अवसर जैसे विषय शामिल थे।

कार्यक्रम में चार पैनल चचाओं और बारह कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इनमें क्षेत्रीय, नीतिगत और सामुदायिक दृष्टिकोण सामने आए। संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, मेटा, गूगल क्लाउड, सीसीएओआई तथा कई शिक्षण संस्थानों के वक्ताओं ने वैश्विक और राष्ट्रीय दृष्टिकोण रखे। इससे इंटरनेट गवर्नेंस पर अंतरराष्ट्रीय विमर्श में भारत के प्रयासों की व्यापक रूपरेखा स्थापित हुई।

फोरम का उद्घाटन करते हुए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (एम. ई. आई. टी. वाई) श्री जितिन प्रसाद ने कहा की 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम ने स्पष्ट किया है

कि डिजिटल क्षेत्र में प्रगति तभी संभव है जब सभी मिलकर कार्य करें। हमारा ध्यान हर नागरिक को सुरक्षित, किफायती और विश्वसनीय इंटरनेट उपलब्ध कराने पर है। मजबूत 5जी कवरेज, सुदृढ़ डिजिटल सार्वजनिक सिस्टम और सहमति-आधारित डेटा संरक्षण अधिनियम के साथ हम ऐसा वातावरण बना रहे हैं जो लोगों की सुरक्षा करता है और नए अवसर खोलता है। हमारे जैसे बड़े देश को वास्तविक साइबर जोखिमों का सामना करना पड़ता है और इनका प्रबंधन केवल सरकार का काम नहीं है। उद्योग, शिक्षाविद और नागरिक समाज—सभी की भूमिका सुरक्षित ऑनलाइन स्पेस बनाने में महत्वपूर्ण है। भारत इंटरनेट गवर्नेंस में वैश्विक सहयोग को निरंतर समर्थन देगा, विशेषकर उन देशों के लिए जिन्हें अभी भी इंटरनेट उपलब्धता में कठिनाइयां हैं। हमारा उद्देश्य साफ है—अंतिम छोर तक पहुंचना और सुनिश्चित करना कि तकनीक का लाभ वास्तव में सभी को मिले।ह्व

एम. ई. आई. टी. वाई के संयुक्त सचिव श्री सुशील पाल ने कहा की 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम भारत की डिजिटल यात्रा में हुई उल्लेखनीय प्रगति और एआई के आगमन से उत्पन्न चुनौतियों—दोनों को रेखांकित करता है। लगभग एक अरब ऑनलाइन उपयोगकताओं के साथ इंडिया स्टैक ने न केवल ग्लोबल साउथ बल्कि विकसित देशों के लिए भी जन-स्तरीय मॉडल प्रस्तुत किया है। हालांकि इस प्रकार का व्यापक पैमाना बड़ी जिम्मेदारी भी लेकर आता है। विश्वास, सुरक्षा और लचीलापन बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि साइबर हमले, भ्रामक जानकारी और डिजिटल तकनीकों के दुरुपयोग का प्रभाव सभी पर पड़ता है। उपयोगकर्ता संरक्षण को मजबूत करना और इंटरनेट का समर्थन करने वाली मूलभूत प्रणालियों को सुदृढ़ करना समन्वित कार्रवाई से ही संभव है। हमारा सामूहिक उद्देश्य सुरक्षित और खुला इंटरनेट सुनिश्चित करना है। जिस पर उपयोगकर्ता भरोसा कर सकें। हमें इंटरनेट के विभिन्न तकनीकी स्तरों पर कार्य करते हुए इंटरनेट लचीलापन बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करना चाहिए।ह्व

एन आई एक्स आई के सीईओ डॉ. देवेश त्यागी ने कहा की 'इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम इस सरल लेकिन शक्तिशाली विश्वास पर खड़ा है कि भारत की इंटरनेट कहानी बहु-हितधारक मॉडल का पालन करने वाले अनेक भागीदारों द्वारा लिखी जाएगी। आईआईजीएफ की विशेषता है, एक ऐसा मंच जहां हर आवाज महत्वपूर्ण है। आईआईजीएफ यात्रा के सबसे गौरवपूर्ण परिणामों में से एक यह रहा है कि सूचित और समावेशी निर्णय-निर्माण के लिए संस्थागत तंत्र मजबूत हुआ है। इंटरनेट के भविष्य, डोमेन नेम्स और नंबर्स, तथा इंटरनेट प्रोटोकॉल एवं मानकों पर विशेष रुचि समूह गहन विशेषज्ञता और व्यापक संवाद को बढ़ावा दे रहे हैं।ह्व उन्होंने आगे कहाः 'एन आई एक्स आई इंटरनेट इंटर्न योजना ने पिछले वर्ष में 10 हजार से अधिक छात्रों तक पहुंच बनाई है और उनमें से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भाग ले रहे हैं। दस से अधिक छात्रों ने पहले ही विश्वभर में भूमिकाएं प्राप्त कर ली हैं। इनमें से अधिकांश नीति ढांचे से संबंधित हैं।ह्व

सत्रों के दौरान प्रतिभागियों ने कहा कि सार्वभौमिक और सार्थक पहुंच भारत की डिजिटल यात्रा के केंद्र में रहनी चाहिए। चचाओं में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना को मजबूत बनाने और सुदृढ़ मानकों और समन्वित प्रयासों के माध्यम से विश्वास निर्माण की आवश्यकता को भी रेखांकित किया गया।

फोरम का समापन इस साझा प्रतिबद्धता के साथ हुआ कि भारत और विश्व के लिए एक अधिक सुरक्षित, समावेशी और लचीला इंटरनेट निर्मित किया जाएगा।

आईआईजीएफ के बारे में

इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम, संयुक्त राष्ट्र इंटरनेट गवर्नेंस फोरम का राष्ट्रीय अध्याय है। वर्ष 2021 में स्थापित इस फोरम में बहु-हितधारक स्वरूप अपनाया गया है। इसमें सरकार, नागरिक समाज, उद्योग, तकनीकी समुदाय और शिक्षाविद समान रूप से योगदान देते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाली 14-सदस्यीय समिति फोरम के कार्यों को दिशा प्रदान करती है। आईआईजीएफ-2025 का आयोजन 27-28 नवंबर को नई दिल्ली में किया गया। उद्घाटन सत्र इंडिया हैबिटैट सेंटर में और दूसरे दिन के सत्र इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुए।

भारत सरकार द्वारा एससीएल मोहाली के आधुनिकीकरण के लिए 4,500 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा; सरकार ने आश्वासन दिया कि इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा

एससीएल में निर्मित 28 छात्रों द्वारा डिजाइन चिप्स को आज सौंपा गया

(जीएनएस)।

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री श्री रवीनीत सिंह ने आज मोहाली के सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी (एससीएल) का दौरा किया ताकि कार्य प्रगति एवं चल रही आधुनिकीकरण गतिविधियों की समीक्षा की जा सके।

यात्रा के दौरान, श्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा किया कि भारत सरकार एससीएल के उन्नयन एवं विस्तार के लिए 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। मंत्री ने आश्वासन दिया, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि एससीएल मोहाली का आधुनिकीकरण होगा और इसका निजीकरण नहीं किया जाएगा। आगे एक लंबी यात्रा है और भारत इसके लिए तैयार है।" मंत्री एससीएल मोहाली में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां 17 शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों द्वारा डिजाइन की गई 28 चिप्स सौंपी गईं।

इन चिप्स को चिप्स टू स्टार्ट-अप (सी2एस) कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (ईडीए) टूल्स का उपयोग करके डिजाइन किया गया है। इसके साथ ही, इस कार्यक्रम के अंतर्गत एससीएल में छात्रों द्वारा डिजाइन की गई कुल 56 चिप्स का निर्माण किया गया है।

मंत्री ने सेमिकंडक्टर प्रोसेस गैलरी और अभ्युत्थान प्रशिक्षण ब्लॉक का भी उद्घाटन किया। सेमिकंडक्टर

प्रोसेस गैलरी में पुरानी पीढ़ी के बनावट उपकरणों से युक्त एक क्लीन रूम लैब प्रदर्शित की गई है। यह छात्रों को एक सेमिकंडक्टर फैब और एटीएमपी सुविधा का वास्तविक अनुभव प्रदान करती है। अभ्युत्थान प्रशिक्षण ब्लॉक में ऑनलाइन और ऑफलाइन सेमिकंडक्टर प्रशिक्षण मॉड्यूल और व्यावहारिक फायर एवं सुरक्षा प्रशिक्षण शामिल हैं।

एससीएल मोहाली के लिए कार्य योजना

श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एससीएल मोहाली के लिए एक स्पष्ट कार्य योजना तैयार किया है और उन्होंने प्रमुख दृष्टि क्षेत्रों को रेखांकित किया है।

एससीएल को आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा और सरकार 4,500 करोड़ रुपये का निवेश करेगी। इसमें उत्पादन क्षमता में व्यापक वृद्धि शामिल होगी, जिसका लक्ष्य मौजूदा स्तर से 100 गुना ज्यादा वेफर्स का उत्पादन करना है।

एससीएल मोहाली छात्रों, शोधकताओं एवं स्टार्ट-अप्स को निर्माण सुविधाएं प्रदान करके समर्थन देना जारी रखेगा, जिससे उनके चिप डिजाइन को वास्तविक सिलिकॉन में परिवर्तित करेगी।

विश्व स्तरीय ईडीए उपकरण

भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां लगभग 300 विश्वविद्यालयों के छात्र सरकारी सहायता से उपलब्ध कराए गए विश्व स्तरीय ईडीए उपकरणों का उपयोग करके सेमीकंडक्टर चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। श्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह पारिस्थितिकी तंत्र विश्व में अद्वितीय है।

उन्होंने बल देते हुए कहा कि एससीएल प्रतिभा विकास, नवाचार और स्टार्टअप्स के लिए एक मंच बना रहेगा। अब तक एससीएल द्वारा प्रदान किया गया यह निर्माण समर्थन भविष्य में और बढ़ेगा।

भविष्य में एससीएल के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए, भारत सरकार ने पंजाब सरकार से 25 एकड़ भूमि आवंटित करने का आग्रह किया है।

अक्टूबर 2025 (वित्त वर्ष 2025-26) तक भारत सरकार के खातों की मासिक समीक्षा

भारत सरकार के अक्टूबर, 2025 तक के मासिक लेखों को समेकित कर रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है। मुख्य अंश नीचे दिए गए हैंः -

भारत सरकार को अक्टूबर, 2025 तक 18,00,475 करोड़ रुपए (कुल प्राप्तियों के संगत बजट अनुमान 2025-26 का 51.5 प्रतिशत) प्राप्त हुए हैं, जिसमें 12,74,301 करोड़ रुपए कर राजस्व (केंद्र को शुद्ध), 4,89,079 करोड़ रुपए गैर-कर राजस्व और 37,095 करोड़ रुपए गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां शामिल हैं। इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा करों के हिस्से के हस्तांतरण के रूप में राज्य सरकारों को 8,34,957 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 1,11,981 करोड़ रुपए अधिक है।

भारत सरकार का कुल व्यय 26,25,619 करोड़ रुपए (तत्कालीन बजट अनुमान 2025-26 का 51.8 प्रतिशत) है, जिसमें से 20,07,876 करोड़ रुपए राजस्व खाते में और 6,17,743 करोड़ रुपए पूंजी खाते में हैं। कुल राजस्व व्यय में से 6,73,715 करोड़ रुपए ब्याज भुगतान के लिए और 2,46,575 करोड़ रुपए प्रमुख सब्सिडी के लिए हैं।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

तत्काल बुकिंग प्रणाली में बदलाव : मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस के लिए ओटीपी प्रमाणीकरण

मुंबई, पश्चिम रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के निदेर्शानुसार तत्काल बुकिंग प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया जा रहा है। अब तत्काल टिकट केवल सिस्टम द्वारा भेजे गए वन टाइम पासवर्ड (OTP) के सत्यापन के बाद ही जारी किए जाएंगे। यह ओटीपी उस मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा, जो यात्री द्वारा बुकिंग के समय दिया जाएगा। ओटीपी का सफल सत्यापन होने पर ही टिकट जारी किया जाएगा।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह डळढ-आधारित तत्काल प्रमाणीकरण प्रणाली 01 दिसम्बर, 2025 की रात 00:00 बजे से लागू होगी और प्रारम्भिक रूप से ट्रेन संख्या 12009/12010 मुंबई सेंट्रल – अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस पर लागू की जाएगी।

नई प्रणाली कंप्यूटरीकृत पीआरएस काउंटरों, अधिकृत एजेंटों, आईआरसीटीसी वेबसाइट तथा आईआरसीटीसी मोबाइल ऐप के माध्यम से की जाने वाली सभी तत्काल बुकिंग पर लागू होगी। इस बदलाव का उद्देश्य तत्काल बुकिंग प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना तथा वास्तविक यात्रियों को तत्काल टिकट प्राप्त करने में बेहतर सुविधा प्रदान करना है।

यात्रियों से अनुरोध है कि वे बुकिंग के समय वैध मोबाइल नंबर अवश्य उपलब्ध कराएँ, ताकि डळढ सत्यापन प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पश्चिम रेलवे द्वारा सभी यात्रियों से इस महत्वपूर्ण बदलाव पर ध्यान देने का आग्रह किया गया है।

एनपीजी ने रेल मंत्रालय की 3 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया

प्रधानमंत्री गतिशक्ति के तहत नेटवर्क योजना समूह की 103वीं बैठक में प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया

(जीएनएस)।

बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए आज नेटवर्क योजना समूह (एनपीजी) की 103वीं बैठक आज आयोजित की गई। बैठक में पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (पीएमजीएस एनएमपी) के अनुरूप, मल्टीमॉडल संपर्क और लॉजिस्टिक्स दक्षता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

एनपीजी ने 3 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया, जिनमें 3 रेल परियोजनाएँ शामिल थीं, जो एकीकृत मल्टीमॉडल बुनियादी ढाँचे, आर्थिक और सामाजिक केंद्रों तक अंतिम-मील संपर्क और 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के पीएम गतिशक्ति सिद्धांतों के अनुरूप थीं। इन पहलों से लॉजिस्टिक्स दक्षता में वृद्धि, यात्रा समय में कमी और परियोजना के तहत आने वाले क्षेत्रों को जरुरी सामाजिक-आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है। इन परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमानित प्रभावों का विवरण नीचे दिया गया है:

रेल मंत्रालय (एमओआर)

बारबेंडा-डमरुघुटू दोहरीकरण और डमरुघुटू-बोकारो तीसरी और चौथी लाइन (पश्चिम बंगाल और झारखंड): रेल मंत्रालय ने बारबेंडा और डमरुघुटू के बीच तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जो पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में 51.761 किलोमीटर लंबी होगी। इस परियोजना में बढ़ती यातायात माँगों को पूरा करने और परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए, दक्षिण पूर्व रेलवे के तहत मौजूदा बारबेंडा-डमरुघुटू-बोकारो स्टील सिटी कॉरिडोर का विस्तार शामिल है।

इस योजना के कार्यों में एक प्रमुख पुल, 18 छोटे पुल, एक रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण और एक मौजूदा लेवल क्रॉसिंग का विस्तार शामिल है। तीसरी लाइन के विकास के हिस्से के रूप में, ब्लॉक केबिन सहित 5 स्टेशन यार्डों का आधुनिकीकरण कार्य किया जाएगा, साथ ही 5 प्रमुख पुलों, 52 छोटे पुलों,

5 आरयूबी और 5 अतिरिक्त लेवल क्रॉसिंग का विस्तार भी किया जाएगा।

यह कॉरिडोर बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल), टाटा स्टील लिमिटेड, डालमिया सीमेंट और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जैसे प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए माल ढुलाई का एक अहम मार्ग है। प्रस्तावित विस्तार से माल ढुलाई में खासा सुधार होगा, भीड़भाड़ और देरी कम होगी, क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और बीबीडीए-डीआरजीयू-बीकेएससी रेलवे कॉरिडोर की समग्र विश्वसनीयता मजबूत होगी।

जमालपुर-मुंगेर-सबदलपुर दोहरी लाइन, जिसमें गंगा नदी पर पुल और जमालपुर अवॉइडिंग लाइन भी शामिल है (बिहार): रेल मंत्रालय ने बिहार में पूर्वी और पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत गंगा नदी पर एक नए पुल और जमालपुर अवॉइडिंग लाइन के साथ जमालपुर-मुंगेर दोहरी लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है। 15 किलोमीटर लंबी इस परियोजना, जिसमें दोहरी लाइन, गंगा पुल और बाईपास अलाइनमेंट शामिल है, को जुलाई 2030 तक पूरा करने की योजना है।

यह गलियारा मुंगेर और बेगूसराय के घनी आबादी वाले गंगा के मैदानों से होकर गुजरता है और उत्तर बिहार तथा बिहार और झारखंड के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्रों के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क के रूप में रणनीतिक महत्व रखता है। इस मार्ग से आईटीसी लिमिटेड (भारत तंबाकू प्रभाग, डेयरी प्लांट, और पैकेजिंग तथा प्रिंटिंग यूनिट), सीताकुंड औद्योगिक क्षेत्र, आयुध गन फैक्टरी, जमालपुर रेलवे वर्कशॉप, भागलपुर मेगा हैंडलूम क्लस्टर, कहलगांव और बरौनी थर्मल पावर स्टेशन, बरौनी रिफाइनरी, हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड, और कांति थर्मल पावर प्लांट सहित प्रमुख औद्योगिक केंद्रों के लिए संपर्क में इजाफा होगा।

इस परियोजना से तेज, सुरक्षित और निर्बाध रेल संपर्क प्रदान करके आर्थिक और सामाजिक विकास की रफ्तार तेज होने की उम्मीद है। यह औद्योगिक और खनन क्षेत्रों के बीच एक अहम कड़ी के रूप में भी काम करेगा, परिवहन लागत को कम करेगा और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करेगा। इसके अलावा, यह परियोजना निर्माण और संचालन दोनों के दौरान, खास तौर पर लोडिंग और अनलोडिंग सुविधाओं, औद्योगिक क्षेत्रों और रेलवे यार्डों में, पर्याप्त प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा करेगी।

संतरागाछी-पंसकुरा-खड़गपुर (पश्चिम बंगाल) के बीच चौथी लाइनः रेल मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल में संतरागाछी और खड़गपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, जिसका मकसद इस क्षेत्र के सबसे जरुरी और अत्यधिक उपयोग किए जाने वाले गलियारों में से एक को मजबूत करना है। यह मार्ग वर्तमान में पर्याप्त माल और यात्री यातायात को संभालता है, जिससे खाद्यान्न, कोयला, सीमेंट, क्लिंकर और स्टील जैसी जरुरी वस्तुओं की आवाजाही आसान होती है, साथ ही रोजाना करीब 115 कोच ट्रेनें भी चलती हैं।

प्रस्तावित चौथी लाइन 110.919 किलोमीटर लंबी होगी, जिसकी कुल लंबाई 133.781 किलोमीटर होगी। यह हावड़ा जिले में 50.319 किलोमीटर, पूर्वी मेदिनीपुर में 26.70 किलोमीटर और पश्चिमी मेदिनीपुर में 33.9 किलोमीटर तक जाएगी। परियोजना के दायरे में 30 स्टेशन यार्डों का आधुनिकीकरण और एक महत्वपूर्ण पुल, 15 बड़े पुल, 100 छोटे पुल और 12 रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) का निर्माण शामिल है। माल ढुलाई की मात्रा पहले वर्ष में 20.37 एमटीपीए से 11वें वर्ष तक 28.12 एमटीपीए तक बढ़ने का अनुमान है, इसलिए भीड़भाड़ कम करने, परिचालन क्षमता बढ़ाने और माल एवं यात्रियों की अधिक विश्वसनीय आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए यह विस्तार बेहद जरुरी है। इस परियोजना से इस महत्वपूर्ण कॉरिडोर पर रेल परिवहन की दक्षता और मजबूती में खासा सुधार होने की उम्मीद है।

बैठक की अध्यक्षता उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के संयुक्त सचिव, लॉजिस्टिक्स ने की।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं डीजीपी /आईजीपी कॉफ्रेंस का उद्घाटन किया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में DGsP/IGsP कॉफ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारण तक, देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन कर उभरी है

अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा

हमने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा के घेरे को मजबूत बनाया है, इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या जो 126 थी, वो घटकर 11 रह गई है

पिछले 40 साल से देश के लिए नासूर बनें 3 हॉटस्पॉट नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर की समस्या के निराकरण का मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है, जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे

हमने NIA, UAPA कानूनों को सुदृढ़ बनाने, तीन नए आपराधिक कानून, नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए हैं

तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूर्णतः लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक होगी

हमने PFI पर बैन लगाकर देशभर में उनके ठिकानों पर छापे मार कर गिरफ्तारियां की, जो केंद्र – राज्य के समन्वय का उत्तम उदाहरण बनी

क्ल्लउ्रीॅल्लीू की अूश्रू८, ड्डीू३५ी की ू'१३८ और अू३ड्डल्ल की २८ल्लीर््८ इन तीन बिंदुओं पर काम करके हम कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार कर रहे हैं

हमें नारकोटिक्स और ड्ड१ॅल्लरीी क्राइम पर 360 डिग्री प्रहार कर ऐसा तंत्र बनाना है कि इस देश में नार्को व्यापारियों और अपराधियों को एक इंच भी जमीन न मिल पाए

अब समय आ गया है कि राज्यों की पुलिस ठउइ के साथ मिलकर नारकोटिक्स के राज्य, राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर के गिरोहों पर कड़ा प्रहार कर उनके आकाओं को जेल में डाले

(जीएनएस)।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में तीन दिवसीय 60वीं DGsP/IGsP कॉफ्रेंस का उद्घाटन किया।

अपने सम्बोधन में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में DGP/IGP कॉफ्रेंस समस्याओं के समाधान, चुनौतियों और रणनीतियों से नीति निर्धारण तक, देश की आंतरिक सुरक्षा के समाधान का फोरम बन कर उभरी है।

गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल प्वाइंट का जिक्र करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया है और इसी का परिणाम है कि 2014 में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी जो आज घटकर सिर्फ 11 रह गई है। केन्द्रीय गृह मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि अगली DGsP/IGsP कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सलवाद की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा।

श्री अमित शाह ने कहा कि पिछले 40 साल से देश नक्सलवाद की समस्या का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के लिए नासूर बने 3 हॉटस्पॉट – नक्सलवाद, नार्थ-ईस्ट और जम्मू-कश्मीर – की समस्या के निराकरण के लिए मोदी सरकार ने स्थायी समाधान दिया है और जल्द ही ये देश के बाकी हिस्सों जैसे बन जाएंगे। गृह मंत्री ने मोदी सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित करते हुए कहा कि नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) कानूनों को सुदृढ़ बनाया गया, तीन नए आपराधिक कानूनों के साथ ही नारकोटिक्स और भगोड़ों के लिए मजबूत कानून बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि तीनों नए आपराधिक कानूनों के पूरी तरह लागू होने के बाद भारत की पुलिसिंग विश्व में सबसे आधुनिक बन जाएगी।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने आतंकवाद और उग्रवाद पर मोदी सरकार की कार्रवाई का जिक्र कहते हुए कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा पॉपुलर फ्रन्ट ऑफ इंडिया (PFI) पर बैन लगाने के बाद देशभर में उसके ठिकानों पर छापे मार कर गिरफ्तारियां की गईं, जो केंद्र – राज्य के समन्वय का उत्तम उदाहरण है।

उन्होंने कहा कि सुरक्षाबलों और पुलिस द्वारा तीन बिंदुओं पर काम कर कट्टरता, उग्रवाद और नारकोटिक्स पर कड़ा प्रहार किया जा रहा है।

भारतीय फामाकीपिया आयोग ने नागालैंड चिकित्सा परिषद, एनएसडीसीए और नागालैंड राज्य फामेर्सी परिषद के साथ तीन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए

(जीएनएस)।

भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान, भारतीय फामाकीपिया आयोग (आईपीसी), गाजियाबाद ने आज नागालैंड चिकित्सा परिषद, नागालैंड राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (एनएसडीसीए), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नागालैंड और राज्य फामेर्सी परिषद, नागालैंड सरकार के साथ तीन समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता फार्मा और सामग्री क्षेत्र में निगरानी पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान हुआ। इसका आयोजन भारतीय फामाकीपिया आयोग गाजियाबाद ने नागालैंड राज्य औषधि नियंत्रण प्रशासन (एनएसडीसीए), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, नागालैंड के सहयोग से किया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एनएसडीसीए के अंतर्गत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं में भारतीय फामाकीपिया संदर्भ पदार्थों और अशुद्धता मानकों के उपयोग को सुगम बनाकर, दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग, फार्मा और सामग्री क्षेत्र में निगरानी गतिविधियों को बढ़ाकर और नागालैंड राज्य में रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाकर जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में आईपीसी के सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करना था।

इस समझौता ज्ञापन पर आईपीसी के सचिव-सह-वैज्ञानिक निदेशक डॉ. वी. कलईसेल्वन ने नागालैंड चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार डॉ. केविलहुली मेयासे, एनएसडीसीए की सहायक औषधि नियंत्रक श्रीमती इमलीला और नागालैंड राज्य फामेर्सी परिषद के रजिस्ट्रार श्री खेले थोरी के साथ इन संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में एएस एंड एफए श्री होवेदा अब्बास और नागालैंड सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव श्री अनूप खिंची भी उपस्थित थे।

नागालैंड औषधि नियंत्रण प्रशासन के साथ समझौता ज्ञापन, उल्लेखनीय रूप से आईपीसी का दूसरा समझौता ज्ञापन है। इसके बाद यूपीएफडीए का दूसरा समझौता ज्ञापन है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी तरह का पहला समझौता ज्ञापन है। नागालैंड चिकित्सा परिषद के साथ समझौता ज्ञापन, देश के किसी भी राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पहला समझौता ज्ञापन है, जो भारतीय फामाकीविजिलेंस कार्यक्रम और भारतीय मैटेरियोविजिलेंस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए है। इसका उद्देश्य देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के स्तर तक रोगी सुरक्षा को बढ़ावा देना है।

नागालैंड सरकार की राज्य फामेर्सी परिषद के साथ समझौता ज्ञापन, दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग, फामाकीविजिलेंस और मैटेरियोविजिलेंस गतिविधियों को बढ़ाने, और रोगी सुरक्षा पहलों को आगे बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश का चौथा राज्य फामेर्सी परिषद है।

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से,

ट्राई ने रुड़की शहर और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्र (एलएसए) के आसपास मोबाइल सेवा ऑपरेटरों की नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्षों का प्रकाशन

प्रविष्टि तिथिः 28 ठडश 2025 12:05ढट ु८ ढक्ह ऊे॑

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अक्टूबर 2025 के दौरान रुड़की शहर और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) लाइसेंसिंग सेवा क्षेत्र (एलएसए) के आस-पास के इलाकों में स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) आयोजित किए हैं। आईडीटी को विभिन्न उपयोग परिवेशों – शहरी क्षेत्रों, हॉटस्पॉट, सार्वजनिक परिवहन केंद्रों आदि में तत्क्षण मोबाइल नेटवर्क प्रदर्शन को मापने के लिए डिजाइन किया गया है।

ट्राई ने अपनी नियुक्त एजेंसी के माध्यम से 7 और 8 अक्टूबर, 2025 के दौरान रुड़की शहर और आसपास के क्षेत्र में 152.8 किलोमीटर का विस्तृत ड्राइव टेस्ट और 2.0 किलोमीटर का पैदल परीक्षण किया। इसमें 2ॠ 3ॠ 4ॠ और 5ॠ तकनीकों का परीक्षण शामिल रहा जो विभिन्न हैंडसेट क्षमताओं वाले उपयोगकर्ताओं के सेवा अनुभव को दशार्ते हैं। आईडीटी के निष्कर्षों को आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधित दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) को सूचित कर दिया गया है।

मूल्यांकित प्रमुख पैरामीटरः

वॉयस सेवाएंः कॉल सेटअप सफलता दर (सीएसएसआर), ड्रॉप कॉल दर (डीसीआर), कॉल सेटअप समय, कॉल साइलेंस दर, ध्वनि गुणवत्ता (एमओएस), कवरेज।

डेटा सेवाएंः डाउनलोड/अपलोड थ्रूपुट, विलंबता, जिटर, पैकेट ड्रॉप दर और वीडियो स्ट्रीमिंग विलंब।

कॉल सेटअप सफलता दर – एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल की ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में कॉल सेटअप सफलता दर क्रमशः 100 प्रतिशत, 95 प्रतिशत, 99.74 प्रतिशत, और 98.48 प्रतिशत है।

ड्रॉप कॉल दर – एयरटेल, बीएसएनएल, आरजेआईएल और वीआईएल में ऑटो-सिलेक्शन मोड (5जी/4जी/3जी/2जी) में ड्रॉप कॉल दर क्रमशः 0 प्रतिशत, 1.84 प्रतिशत, 0 प्रतिशत और 0 प्रतिशत है।

प्रमुख क्यूओएस मापदंडों के विरुद्ध प्रदर्शन का सारांश

सीएसएसआर : कॉल सेटअप सफलता दर (% में), सीएसटी : कॉल सेटअप समय (मिली सेकंड में), डीसीआर : ड्रॉप कॉल दर (% में) और एमओएस : औसत राय स्कोर।

ये परीक्षण तत्क्षण परिवेश में ट्राई-अंशांकित उपकरणों और मानकीकृत प्रोटोकॉल का उपयोग करके किए गए थे।

विस्तृत रिपोर्ट ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए श्री संजय कुमार गुप्ता, सलाहकार (क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल) ट्राई से ईमेलः या दूरभाष क्रमांक +91-755-2575501 पर संपर्क किया जा सकता है।

ट्राई ने सीकर शहर और आसपास के क्षेत्र में जयपुर-चूरू राजमार्ग को कवर करने वाले मोबाइल नेटवर्क गुणवत्ता का आकलन किया

दूसरी तरफ भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने अक्टूबर 2025 के दौरान जयपुर-चूरू राजमार्ग और सीकर शहर तथा सालासर और रींगस (राजस्थान में) सहित आसपास के क्षेत्रों में किए गए स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट (आईडीटी) के निष्कर्ष जारी किए हैं। इस ड्राइव टेस्ट का उद्देश्य दूरसंचार सेवा प्रदाताओं (टीएसपी) द्वारा प्रदान की जाने वाली मोबाइल नेटवर्क सेवाओं (वॉयस और डेटा दोनों) की वास्तविक गुणवत्ता का आकलन और सत्यापन करना है।

स्वतंत्र ड्राइव टेस्ट के दौरान, ट्राई सभी सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों जैसे कॉल सेटअप सफलता दर, डेटा डाउनलोड और अपलोड गति, ध्वनि गुणवत्ता आदि पर लाइव प्रदर्शन डेटा एकत्र करता है।

नॉर्वेजियन फिल्म "सेफ हाउस" ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 56वें संस्करण में प्रतिष्ठित आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक जीता

"सेफ हाउस" अराजकता के बीच मानवता को बनाए रखने का प्रयास करने वालों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करता है

एरिक स्वेन्सन द्वारा निर्देशित नॉर्वेजियन फिल्म 'सेफ हाउसह्व को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी 2025) के 56वें संस्करण में आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार शांति, अहिंसा एवं अंतर-सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देने वाले सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। इस फिल्म के निर्देशक एरिक स्वेन्सन की ओर से आईसीएफटी-यूनेस्को पेरिस के मानद प्रतिनिधि मनोज कदम ने प्राप्त किया और एनएफडीसी के एमडी श्री प्रकाश मगदुम द्वारा प्रदान किया गया।

"सेफ हाउस" 2013 में मध्य अफ्रीकी गणराज्य में हुए गृहयुद्ध के दौरान बांगुई स्थित डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अस्पताल में घटित लगातार 15 घंटों की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित एक मार्मिक, मानवीय और गहन भावनात्मक ड्रामा है। फिल्म युद्धग्रस्त क्षेत्र में कार्यरत सहायता कर्मियों की उस टीम पर केंद्रित है, जो अराजकता और हिंसा के बीच असंभव निर्णयों, सीमित संसाधनों और बढ़ते दबाव के बीच मानव जीवन बचाने के लिए प्रयासरत रहती है। यह देखभाल, साहस, कर्तव्य और ज़िम्मेदारी जैसे नैतिक मूल्यों की गहराई से पड़ताल करती है। वास्तविक समय में आगे बढ़ती इसकी कहानी, दर्शकों को न केवल युद्ध क्षेत्र की भयावह वास्तविकताओं से रूबरू कराती है, बल्कि उन लोगों के लचीलेपन, धैर्य और करुणा को भी उजागर करती है।

अंतर्राष्ट्रीय फिल्म, टेलीविजन और दृश्य-श्रव्य संचार परिषद (आईसीएफटी) और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित यह पुरस्कार उन फिल्मों को सम्मानित करता है, जो सहिष्णुता, अंतर-सांस्कृतिक संवाद एवं शांति की संस्कृति के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती हैं।

निर्णायक मंडल ने "सेफ हाउस" की अत्यधिक दबाव में नैतिक साहस एवं मानवीय मूल्यों के सशक्त व प्रामाणिक चित्रण के साथ-साथ सांस्कृतिक सीमाओं को पार करने और दर्शकों को गहरे भावनात्मक स्तर पर जोड़ने की क्षमता के लिए सराहना की। सच्ची घटनाओं पर आधारित इस फिल्म की वास्तविक कथा, संघर्ष क्षेत्रों में सहायताकर्मियों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को उजागर करती है और करुणा, जिम्मेदारी तथा मानव जीवन की पवित्रता जैसे सार्वभौमिक विषयों पर बल देती है। इसकी संयमित, रहस्यपूर्ण कहानी और क्रिस्टीन कुजाथ थोर्प के मुख्य अभिनय ने इसके प्रभाव को और सशक्त किया है, जिससे यह आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक के लिए एक आकर्षक पसंद बनी।

नई पीढ़ी के नॉर्वेजियन फिल्म निमार्ता एरिक स्वेन्सन अपनी विशिष्ट शैली और संवेदनशील कहानी कहने के लिए पहले से ही अंतरराष्ट्रीय पहचान हासिल कर चुके हैं। उनकी चर्चित फि ल्में "वन नाइट इन ओस्लो" और "हाराजुकु" कई प्रतिष्ठित समारोहों में सराही गईं। उनकी नवीनतम फिल्म "सेफ हाउस" का विश्व प्रीमियर 48वें गोटेबोर्ग फिल्म महोत्सव 2025 में उद्घाटन फिल्म के रूप में हुआ, जहां इसे दर्शकों की व्यापक प्रशंसा मिली और सर्वश्रेष्ठ नॉर्डिक फिल्म के लिए ऑडियंस ड्रैगन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

यह पुरस्कार इफ्फी के वैश्विक सिनेमा को प्रदर्शित करने के मिशन को रेखांकित करता है, जो संस्कृतियों के बीच करुणा, एकता एवं संवाद को बढ़ावा देता है और समाजों के बीच सेतु बनाने के लिए सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति की पुष्टि करता है।

आईसीएफटी – यूनेस्को गांधी पदक के बारे में

46वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के दौरान प्रारंभ किया गया आईसीएफटी-यूनेस्को गांधी पदक उन फिल्मों को सम्मानित करने के लिए स्थापित किया गया है, जो उत्कृष्ट कलात्मकता एवं उच्च सिनेमाई मानकों को प्रदर्शित करने के साथ-साथ समाज के महत्वपूर्ण और समकालीन मुद्दों पर नैतिक विमर्श को प्रोत्साहित करती हैं। यह प्रतिष्ठित पुरस्कार सिनेमा की परिवर्तनकारी शक्ति के माध्यम से मानवता के साझा मूल्यों, शांति, करुणा और संवाद की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।

आईसीएफटी यूनेस्को गांधी पदक महज एक पुरस्कार नहीं है; यह प्रेरणा देने, शिक्षित करने और एकजुट करने की फिल्म की शक्ति का उत्सव है।

इफ्फी के बारे में जानकारी

वर्ष 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (इफ्फी) दक्षिण एशिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित सिनेमा उत्सवों में से एक है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) गोवा सरकार के गोवा मनोरंजन सोसायटी (ईएसजी) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित यह महोत्सव आज एक वैश्विक सिनेमाई मंच के रूप में पहचान रखता है। यहां पर पुनर्स्थापित क्लासिक फि ल्में साहसिक प्रयोगधर्मिता से मिलती हैं और दिग्गज कलाकारों के साथ उभरते प्रतिभाशाली फिल्मकार भी समान रूप से मंच साझा करते हैं। इफ्फी की सबसे बड़ी खासियत उसका विविधतापूर्ण आकर्षक मिश्रण है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रदर्शनियां, मास्टरक्लास, विशेष श्रद्धांजली कार्यक्रम और ऊर्जा से भरा वेव्स फिल्म बाजार शामिल हैं। यहां पर नए विचार, महत्त्वपूर्ण सौदे और वैश्विक सहयोग लगातार जन्म लेते हैं। 20 से 28 नवंबर तक गोवा की मनमोहक तटीय पृष्ठभूमि में आयोजित हुए इस महोत्सव के 56वें संस्करण ने भाषाओं, शैलियों, रचनात्मक नवाचारों और नई ध्वनियों की चकाचौंध भरी श्रृंखला प्रस्तुत की, जो विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा की रचनात्मक क्षमता एवं सांस्कृतिक प्रभाव का एक गहन व भव्य उत्सव है।

भव्य आतिथ्य एवं स्वागत के साथ आयोजित होगा काशी-तमिल संगमम् कार्यक्रम

तमिल संगमम् कार्यक्रम के तहत सदस्य दलों का प्रथम जत्था 04 दिसम्बर को पहुंचेगा प्रयागराज

(जीएनएस)।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को संगम सभागार में काशी तमिल संगमम् कार्यक्रम के आयोजन के सम्बंध में बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी ने आयोजित होने वाले काशी-तमिल संगमम् कार्यक्रम को सुव्यवस्थित, भव्य एवं आकर्षक रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है। उन्होंने समागम के दौरान सम्बंधित स्थानों पर विधि व्यवस्था के साथ-साथ अन्य आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने हेतु अधिकारियों को उनके कार्य दायित्वों का आवंटन करते हुए उनसे सम्बंधित कार्यों/तैयारियों को 01 दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराये जाने का निर्देश दिया है। काशी-तमिल संगमम् कार्यक्रम के तहत समागम में 07 समूहों में लोग प्रयागराज आयेंगे तथा विषयवस्तु से सम्बंधित स्थानों, शहर के प्रमुख मंदिरों, स्थलों का भ्रमण करेंगे। समागम का प्रथम दल 04 दिसम्बर को प्रयागराज आयेगा और इसके बाद क्रमशः छः समागम दल दिनांक 06, 08, 10, 12, 14 एवं 16 दिसम्बर तिथियों को प्रयागराज आना प्रस्तावित है।

जिलाधिकारी ने कार्यक्रम में आने वाले दलों का भव्य रूप से आतिथ्य एवं स्वागत करने के लिए कहा है। उन्होंने संगम क्षेत्र में आयोजित होने वाले कार्यक्रम के अवसर पर सुसज्जित बोटों, मोबाइल टॉयलेट, पेयजल, पार्किंग सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थायें समय से सुनिश्चित कराये जाने के लिए सम्बंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है। इस अवसर पर विद्यालयों में काशी-तमिल संगमम् विषय पर विभिन्न कार्यक्रमों एवं प्रतियोगिताओं का आयोजन भी कराया जायेगा। प्रयागराज आगमन के अवसर पर टीम के सदस्य सर्वप्रथम संगम जायेंगे, वहां पर संगम स्नान, बोटिंग, लेटे हुए हनुमान जी का दर्शन, श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर दर्शन सहित अन्य स्थलों पर जायेंगे।

जिलाधिकारी ने काशी तमिल संगमम् कार्यक्रम को सकुशल एवं सुव्यवस्थित रूप से सम्पन्न कराये जाने के लिए मजिस्टेज्टों सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किए है। जिलाधिकारी ने नगर निगम को संगम क्षेत्र में साफ-सफाई, मुख्य चिकित्साधिकारी को मेडिकल टीम तथा एम्बुलेंस की व्यवस्था, सुरक्षा की चाक-चौबंद व्यवस्था के लिए पुलिस कमिंर्यों के साथ ही महिला पुलिस कमिंर्यों की तैनाती भी करने के लिए कहा है। जिलाधिकारी ने संगम पर पर्याप्त संख्या में नावों की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराये जाने के लिए कहा है साथ ही साथ उन्होंने तमिल भाषा के जानकार वालंटियर्स की भी व्यवस्था किए जाने के लिए कहा है। उन्होंने कार्यक्रम के लिए यातायात, पार्किंग, बॉर्डर स्कार्ट सहित सभी व्यवस्थायें सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए है। इस अवसर पर माघ मेला अधिकारी/उपाध्यक्ष प्रयागराज विकास प्राधिकरण श्री ऋषिराज, सचिव पीडीए श्री अजित सिंह, सिटी मजिस्टेज्ट श्री विनोद सिंह, जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक सहित सभी सम्बंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध होती हैंः राष्ट्रपति

(जीएनएस)।

लखनऊ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा शुक्रवार को लखनऊ में आयोजित विश्व एकता एवं विश्वास के लिए ध्यान (योग) के राज्य स्तरीय उद्घाटन समारोह में भाग लेते हुए राजयोग के जरिए आध्यात्मिक चेतना के विकास पर बल दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विश्वास वहीं टिकता है, जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध होती हैं। उन्होंने कहा कि सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। राष्ट्रपति मुर्मु के अनुसार, शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव बनती है कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित होते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'ओम शांतिह्व के संबोधन से अपने वक्तव्य की शुरूआत की। उन्होंने कहा कि भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव वसुधैव कुटुम्बकम् का संदेश विश्व को दिया है, जिसका भाव यह है कि सारा विश्व एक परिवार है। आज जब विश्व कई प्रकार की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह विचार और अधिक प्रासंगिक बन जाता है। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए यह अभियान प्रभावी योगदान देगा। उन्होंने कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए ब्रह्मकुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि

भारत सरकार समाज को अधिक समावेशी, शांतिपूर्ण और मूल्य-आधारित बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। योग एवं ध्यान को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना तथा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन का नेतृत्व भी इसी का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मूल्य-आधारित शिक्षा तथा जीवन पोषण जैसे तथ्यों का समावेशन इसी दिशा का प्रयास है। भारत सरकार ने मिशन लाइफ अभियान की शुरूआत की है, जो पर्यावरण के प्रति जागरूकता प्रसारित करने का अभियान है। महिला सम्मान, आत्मनिर्भरता और सामाजिक समावेश के लिए विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। वर्ष 2023 में भारत में हुए जी-20 समिट के आयोजन का उल्लेख करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि समिट का थीम था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। उन्होंने कहा कि ये पहल इस महत्वपूर्ण संदेश को मजबूत करती हैं कि मानवता का भविष्य मानव-मूल्यों, संवाद, विश्वास और आध्यात्मिक चेतना से सुरक्षित और उज्ज्वल होगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में विज्ञान और तकनीक के बल पर मानवता ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज का युग सूचना, प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और अंतरिक्ष अनुसंधान का युग है। इन क्रांतिकारी परिवर्तनों ने मानव जीवन को अधिक सुविधाजनक, सुगम तथा संसाधन-संपन्न बनाया है। राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि आज का मानव पहले की अपेक्षा अधिक शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम है। उसके पास आगे बढ़ने के अनेक अवसर हैं, लेकिन समाज में तकनीकी उन्नति के साथ तनाव, असुरक्षा, अविश्वास और एकाकीपन भी बढ़ रहा है। आज आवश्यक है कि हम केवल आगे बढ़ने की ही नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने की भी यात्रा प्रारंभ करें। इसी ह्यस्वह्ल से साक्षात्कार को सुगम बनाने का कदम ब्रह्मकुमारीज ने उठाया है, जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि हर मनुष्य चाहता है कि वह दूसरों पर विश्वास करे, लेकिन विश्वास वहीं टिकता है जहां मन शांत, विचार स्वस्थ और भावनाएं शुद्ध हों। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ क्षण रुककर स्वयं से संवाद करते हैं, तो यह अनुभव होता है कि शांति और आनंद किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। जब आत्मिक चेतना जागृत होती है, तो प्रेम, भाईचारा, करुणा और एकता स्वतः जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। शांत और स्थिर मन समाज में शांति का बीज बोता है और वहीं से विश्व शांति और विश्व एकता की नींव रखी जाती है। सशक्त आत्मा ही विश्व एकता की संकल्पना को साकार करने की आधारशिला रही है। ब्रह्मकुमारीज संस्था द्वारा विश्व शांति, मानवीय मूल्य, नारी शक्ति, आत्मिक जागृति, शिक्षा और ध्यान के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयास वास्तव में प्रेरक और प्रशंसनीय हैं। इस सेवा के लिए सभी का हृदय से धन्यवाद। उन्होंने आह्वान किया कि आइए, शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्म में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि वेह्व

बीसलपुर हाईवेः ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रक की जोरदार टक्कर, नांद गांव के पास सुबह हादसा

(जीएनएस)।

पीलीभीत,28 नवंबर, बीसलपुर-बिलसंडा हाईवे पर नांद गांव से 1 किमी दूर आज सुबह तड़के ट्रैक्टर-ट्रॉली व ट्रक की सीधी भिड़ंत। गन्ना लदी ट्रॉली मवैया सेंटर से चीनी मिल मकसूदापुर जा रही, चावल बोरियों से भरा ट्रक बरेली दिशा में। टक्कर इतनी जोरदार कि दोनों वाहन सड़क पर रुके, लेकिन चमत्कारिक रूप से ड्राइवर सुरक्षित। हल्की चोटें लगीं, प्रत्यक्षदर्शी बोले, "सुबह की धुंध में नजर न आई।" ट्रैक्टर मवैया निवासी नन्हेंलाल का।

मौके पर लोग पहुंचे, लेकिन ड्राइवर पहले ही उतर चुके। पुलिस ने वाहनों को हटवाया, ट्रैफिक बहाल। एसपी अभिषेक यादव ने निर्देश - "हाईवे पर सतर्कता, धुंध में स्लो ड्राइव।" इलाके में राहत।

हरे भरे पेड़ों का परमिट देकर हरियाली को खत्म करने में लगा वन विभाग

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। जिले को हरा भरा बनाने का दंभ तो हर साल भरा जाता है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। वन विभाग स्वयं आम के हरे भरे पेड़ो का परमिट देकर हरियाली पर आरा चलवा रहा है। बताते चले कि पहले क्षेत्र मे तैनात रहे वनगार्ड सतीश मिश्रा जब से वन दरोगा बनकर इसी क्षेत्र मे तैनाती पाये है तब से वन माफिया ठेकेदारों के हौसले बुलंद हैं ।

बताते चले कि मैंगो बेल्ट के रूप मे जाने जाने वाले मसौली क्षेत्र मे जिस तरह हरे भरे आम के पेड़ो पर आरा चलाया जा रहा है जिससे वह दिन दूर नही जब अमुक अमुक वैराइटी की आम की बागे क्षेत्र मे उजड़ा चमन हो जायेगा जिसका सीधा असर पर्यावरण एवं स्थानीय पहचान पर पड़ेगा। बड़ी बड़ी बागो को काट कर ।

हरियाली को मुनाफे की जमीन मे मिटाया जा रहा है कहने को तो हाईकोर्ट ने आम के हरे पेड़ों को काटने पर पूरे प्रदेश में रोक लगा दी है लेकिन बागों का शहर कहे जाने वाले इस क्षेत्र में कुल्हाड़ों का आतंक अपने चरम पर है। हरियाली का सफाया कर यहां कंक्रीट की इमारतें खड़ी की योजनाएँ

बनाई जा रही है । शहरी विकास की दृष्टि से तेजी से बदल रहे बाराबंकी में हरियाली पर शामत जैसी आ गई है। वन व पुलिसकर्मियों की मिलीभगत से जिले में हरे पेड़ों की अवैध कटान पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

(वन विभाग दे रहा है हरे पेड़ो का परमिट ठेकेदार एक परमिट पर साफ कर रहे पूरी पूरी बागे)

नियम है कि हरे पेड़ों की न कटान हो और न ही कटान के लिए परमिट जारी किया जाए। इसके बावजूद भी हरे पेड़ों को रोगग्रस्त दिखाकर परमिट जारी कर दिया जाता है। एक पेड़ के बजाय ठेकेदार अधिक पेड़ों की कटान कर लेते हैं। यह सब वन विभाग और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से होता है। नियम है कि सूखे पेड़ का ही परमिट जारी किया जाए। लेकिन प्रभागीय वनाधिकारी बिना जाँच पड़ताल किये रेवडी की तरह हरे पेड़ो का परमिट दे रहे है और ठेकेदार एक पेड़ की परमिट पर दर्जनों पेड़ को काट कर खुले आम वन विभाग को चुनौती दे रहे है बीते एक माह के अंदर थाना मसौली एव सफदरगंज मे अंनगिनत आम के हरे भरे पेडो का कटान हो चुका है। शिकायत होने पर वन विभाग एक दो पेड़ो पर जुमार्ना कर वाहवाही लूट लेती है।

विगत माह सफदरगंज थाना क्षेत्र के ग्राम सिकंदरपुर मे गांव के पश्चिम रोड पर सत्यवान वर्मा की नई नवधा.आम मे 5 पेड़ के परमिट पर बाग के 23 पेड़ो में पर आरा चलाया गया विगत दिनों शिकायत होने पर वन क्षेत्राधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जांच कर मात्र आठ पेड़ों के पुष्टि कर झूठि रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया गया।

मसौली थाना के ग्राम बड़ागांव में फावाद मिंया की बाग मे एक माह में 30 आम के पेड़ बगैर परमिट के काट कर गायब कर दिये गिर इसी गांव में मालिन बाग में तीन आम के पेड़ तमोली की बाग में तीन आम के पेड़ हनुमान मंदिर के पूर्व दिशा में बिलास रावत की बाग में एक आम का पेंड काटकर गयाब कर दिया गया ग्राम रहरामऊ निवासी जामी मियां की बाग में बगैर परमिट के सात आम पेड़ काट कर गयाब कर दिया गया जो सोचनीय विषय है इस प्रकरण में वन क्षेत्राधिकारी द्वारा जांच किया तो शिकायत सही पाई गई लेकिन कार्यवाही अभी तक जिरो है ऐसे में न सिर्फ जिले को हरा भरा बनाने का मकसद अधूरा रहता है,

उधर, डीएफओ आकाशदीप बंधावन का कहना है कि जहां पर भी पेड़ों के कटान सूचना मिलती है, टीम भेजकर कार्रवाई कराई जाती है। सूखे पेड़ों का ही परमिट जारी किया जाता है।

(एक प्राइवेट फारेस्ट गार्ड के इशारे पर होती कटान)

बताते चले कि क्षेत्रीय वन दारोगा सतीश मिश्रा अपना एक निजी मौर्या नामक गार्ड रख रखा है जिसके इशारे पर इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हरे पेड़ों की कटान होती है। पेड़ों की कटान इस गार्ड के बिना कोई नहीं करा सकता। कई बार गार्ड का हरे पेड़ों की कटान में नाम आया, लेकिन हर बार सतीश मिश्रा की सेटिंग से बचा लिया जाता है। अभी दो दिन पूर्व बड़ागांव बांसा रोड पर बडागांव में हनुमान मंदिर के सामने आम कि बाग में चल रही प्लाटिंग में लगे बाग में हरे भरे चार आम पेड़ों का परमिट देकर कटवा दिया गया ।

जंगल में बुजुर्ग जीवनलाल का रक्तरंजित शव, आत्महत्या संदेह

(जीएनएस)।

पीलीभीत,28 नवंबर गजरौला कला थाना क्षेत्र के माला रेंज गड़ा बीट 135ए में शुक्रवार सुबह 8 बजे जामुन पेड़ के नीचे 50 वर्षीय जीवनलाल (पुत्र जानकी प्रसाद, बैजू नगर) का रक्तरंजित शव संदिग्ध हालत में मिला। पास से जूते व दरांती बरामद। वन दरोगा रामभरत यादव ने बताया, "गुरुवार दोपहर से लापता, खेत जंगल से लगा - तलाश चली। ग्रामीणों ने सूचना दी, भीड़ लगी।"

थानाध्यक्ष ब्रजवीर सिंह ने साक्ष्य जुटाए। प्रथमदृष्टया आत्महत्या, लेकिन ढट रिपोर्ट से पुष्टि। चचेरा भाई माखनलाल बोले, "दोपहर गायब, शाम तलाश। कर्ज बोझ से तनाव।" परिवारः पत्नी कमला देवी, बेटी गीता देवी, बेटा प्रेमपाल, भाई कालीचरण - शोकाकुल। पुलिस ने शव पीएम के लिए भेजा, जांच जारी।

एसडीएम महिपाल सिंह ने भैरव कला में एसआईआर निरीक्षण किया

SDM महिपाल सिंह ने भैरव कला में SIR निरीक्षण किया, बूथ 322/323 पर कैंप लगाकर वोटर जागरूक - फॉर्म भरें या वोट गंवाएं, इछड घर-घर पहुंचे, आधार-वोटर लिस्ट संलग्न करें

(जीएनएस)।

पीलीभीत,28 नवंबर कलीनगर तहसील क्षेत्र के भैरव कला में SDM महिपाल सिंह ने विशेष प्रगाढ़ मतदाता पुनरीक्षण (रक्फ़) कार्य का जायजा लिया। प्राथमिक विद्यालय के बूथ 322-323 पर कैंप चेक किया, जहां वोटर आईडी संशोधन करवाया। BLO, लेखपाल, ग्राम प्रधान रामप्रताप पासवान व प्रत्याशी शेखर यादव मौजूद।

SDM बोले, "फॉर्म BLO को जमा करें, न भरा तो चक्कर लगेंगे व वोट न बनेगा। समस्या हो तो मेरे नंबर पर कॉल।" शिविर में कोटेदार लीलाधर, BLO रमेश-सुशील-पप्पू सागर, रोजगार सेवक राजेश यादव शामिल। BLO घर-घर फॉर्म भर-वितरित कर रहे, आधार व वोटर लिस्ट कॉपी लगाएं। DM निर्देश - शाम तक ऑनलाइन अपलोड, अगले दिन बाकी पूरा। जागरूकता अभियान तेज।

राम सिंह उर्फ भुल्लन वर्मा पर विश्वास जताते हुए पार्टी का नया जिलाध्यक्ष बनाया गया

(जीएनएस)।

मसौली बाराबंकी। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेर्तत्व ने पुराने भाजपाई जिला पंचायत सदस्य कस्बा मसौली निवासी राम सिंह उर्फ भुल्लन वर्मा पर विश्वास जताते हुए पार्टी का नया जिलाध्यक्ष बनाया है। पहली बार पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कुर्मी बिरादरी को जिलाध्यक्ष की कमान सौंपी है। जिसे लेकर भाजपाइयों में खुशी है। प्रदेश कार्यालय से सूची जारी होते ही सोशल मीडिया के साथ ही उनके घर पहुंच कर बधाई देने वालों का तांता लग गया। पैतृक गांव और पार्टी कार्यालय पर समर्थकों ने फूल मालाओं से जमकर स्वागत किया।

वर्ष 1989 से भारतीय जनता पार्टी मे लगन एव निष्ठा से कार्य करने वाले राम सिंह वर्मा उर्फ भुल्लन को बाराबंकी जिले का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है वर्ष 1990 मे बूथ अध्यक्ष बने रामसिंह वर्मा ने हमेशा पार्टी के ईमानदारी से काम किया कई बार इनके ऊपर राजनीतिक पार्टियों का दबाव डाला गया की पार्टी छोड़ दो हमारे साथ आ जाओ लेकिन भुल्लन वर्मा ने भारतीय जनता पार्टी से हटकर किसी अन्य दल को कभी सपोर्ट नहीं किया हमेशा हिंदुत्व के लिए तत्पर रहे वर्ष 2010 मे जिला नेर्तत्व ने जिला उपाध्यक्ष व वर्ष 2020 जिला महामंत्री की जिम्मेदारी दी वर्तमान समय मे जिला महामंत्री के साथ साथ जिला पंचायत सदस्य भी है बीती रात्रि प्रदेश नेर्तत्व द्वारा जारी जिलाध्यक्षों की सूची मे बाराबंकी जिलाध्यक्ष पद पर रामसिंह वर्मा के मनोनीत होने की जानकारी मिलते ही

समर्थकों, कार्यकताओं की पैतृक गांव मोहल्ला भूलीगंज कस्बा मसौली मे भीड़ लग गयी और लोगो ने मुँह मीठा कराते हुए माला पहना कर स्वागत किया।

(दूसरी बार कस्बा मसौली को मिली भाजपा की जिलाध्यक्षी)

भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष रामसिंह उर्फ भुल्लन वर्मा ने राष्ट्रीय एव प्रांतीय नेर्तत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी के शीर्ष नेताओं ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाया जायेगा तथा मेरा लक्ष्य है आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव मे जनपद की सभी 6 की 6 विधानसभाओं मे कमल खिलाना उन्होंने कहा कि पार्टी के नेताओं ने कस्बा मसौली को दूसरी बार जिलाध्यक्ष की कमान सौपी है इससे पूर्व वर्ष 2010 मे पूर्व विधायक शरद अवस्थी जिलाध्यक्ष रह चुके है। गुरुवार को जिला पंचायत अध्यक्ष राजरानी रावत, विधान परिषद सदस्य अंगद सिंह, रामबाबू द्विवेदी, अमित वर्मा, मंडल अध्यक्ष रंजीत कुमार वर्मा, ठाकुर हुकुम सिंह, नेत्र सर्जन डॉ विवेक वर्मा, राजकुमार सोनी, देवी शंकर सोनी, राजेश वर्मा, रवि वर्मा, मोहित हिन्दू प्रेमनंद वर्मा, केवल प्रसाद वर्मा, अरुण कुमार सहित तमाम लोगो ने माला पहनाकर बधाई दी।

पीलीभीतः नगीपुर अकोला ग्राम पंचायत में रोड निर्माण घोटाला, प्रधान हरिओम ने 3.40 लाख हजम किए-विकास का दावा झूठा!

(जीएनएस)।

बीसलपुर। जिला पीलीभीत के तहसील बीसलपुर अंतर्गत ग्राम नगीपुर अकोला में ग्राम प्रधान हरिओम पर 2021 में रोड निर्माण के नाम पर 3,40,000 रुपये के घोटाले का गंभीर आरोप लगा है। दो किस्तों में जारी हुए फंड के बावजूद गांव में सड़क का निर्माण न होने से ग्रामीणों में रोष फैल गया है। मामला पंचायती राज विभाग तक पहुंचा है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव की मुख्य राह आज भी कीचड़ और गड्ढों से भरी पड़ी है। "बारिश में तो पार करना मुश्किल हो जाता है। बच्चे स्कूल जाते समय गिरते हैं, लेकिन

प्रधान का दावा है कि काम पूरा हो गया, न मजदूरों को भुगतान का रिकॉर्ड, न सामग्री की खरीद के बिल सही। प्रधान ने फर्जी ठेकेदारों के नाम पर पैसे ट्रांसफर किए, जो जांच के दायरे में हैं।

यह मामला पहला नहीं है। पीलीभीत जिले में रोड निर्माण घोटालों की भरमार रही है—जैसे पूरनपुर ब्लॉक में 1 करोड़ की सड़क बाढ़ में धुल गई, या गजरौला में 90 लाख की सड़क हाथ से उखड़ गई। नगीपुर अकोला में शिकायतें 2022 से ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर (बीडीओ) बीसलपुर को दी जा रही हैं, लेकिन ऑडिट नहीं हुआ। ग्राम सचिव ने भी मामले को दबाने की कोशिश की।

"प्रधान चुनाव लड़ने से पहले विकास का वादा किया, लेकिन 4 साल बाद भी सड़क नहीं। ये भ्रष्टाचार जिले की छवि खराब कर रहा,